

THE
PARLIAMENTARY DEBATES
OFFICIAL REPORT IN THE SIXTEENTH
SESSION OF THE RAJYA SABHA. Commencing on the 18th
March 1957

1

RAJYA SABHA

Monday, 18th March 1957

The House met at fifteen minutes past twelve of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

MEMBER SWORN

Shri S. K. Dey (Delhi).

PAPERS LAID ON THE TABLE

PRESIDENT'S ADDRESS

SECRETARY: Sir, I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 18th March 1957:

(Text of the President's Address in Hindi)

संसद् के सदस्यगण, आज मैं पूरे एक वर्ष के बाद आपके सामने अभिभाषण कर रहा हूँ। यह वर्ष हमारे देश के लिये और विश्व के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्ण रहा है। हम ऐसे समय एकत्र हुए हैं जब कि देश भर में ग्राम चुनाव चल रहे हैं और इन के परिणाम-स्वरूप नई संसद् की स्थापना होने जा रही है। इस संसद् के सम्मुख कुछ कहने का मेरे लिए यह अंतिम अवसर है। अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में आप में से कुछ नई संसद् में भी आयेंगे और संभवतः कुछ सदस्यगण नई संसद

2

में नहीं आयेंगे। आप का कार्यक्षेत्र कहीं भी हो, मुझे इस में संदेह नहीं कि जो कुछ भी आप करेंगे वह इस देश के निर्माण-सम्बन्धी महान् कार्य के हित में होगा। मैं आप के कार्य में सफलता और आप की सम्पन्नता की कामना करता हूँ।

२. पिछली बार जब मैंने आप के सामने अभिभाषण दिया था, तब से संसार ने, विशेषकर मध्यपूर्व ने, तनाव की स्थिति का सामना किया है और एक ऐसा संघर्ष भी देखा है जिस का अन्तिम रूप मिस्र पर आक्रमण हुआ। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और संसार के जनमत के फलस्वरूप आक्रमणकारी सेनाओं को मिस्र से हटा लिया गया, किन्तु इस संघर्ष से मिस्र को भारी क्षति ही नहीं उठानी पड़ी बल्कि ऐसे समय जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा था तनाव में वृद्धि हुई। इन परिस्थितियों के कारण बहुत सी समस्याएँ पैदा हो गई हैं जिन्हें अब सुलझाना होगा। इन समस्याओं से हमारा भी गहरा सम्बन्ध है क्योंकि विश्व-शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में हमारी दिलचस्पी है और हमें अपने हितों की भी रक्षा करनी है। इसलिए इन कठिनाइयों को सुलझाने में हम ने योगदान देने की चेष्टा की। इस प्रकार हमारे देश ने अपने ऊपर भारी दायित्व लिए हैं जिन में संयुक्त राष्ट्र आपत्कालिक सेना में सम्मिलित होना भी शामिल है। यह सेना संयुक्त राष्ट्र की साधारणसभा की निर्णय के

अनुसार और आक्रमणकारी सेनाओं के वापसी-सम्बन्धी प्रस्ताव के अन्तर्गत संगठित की गई थी ।

३. मध्य यूरोप में हंगरी में घटने वाली घटनाओं से हमें बहुत घबराहट हुई और दूसरे मामलों की तरह इस मामले में भी हम ने विदेशी सेनाओं की वापसी के लिए और राष्ट्रीय आन्दोलनों के दमन के लिए उन के प्रयोग के विरुद्ध आवाज उठाई । इस के साथ ही विभिन्न अवसरों पर इस समस्या का हल ढूँढ़ने में हम ने भरसक सहायता करने की चेष्टा की और हंगरी के लोगों की लाक्षणिक सहायता के रूप में उन के प्रति सहानुभूति प्रकट की ।

४. विश्व-शान्ति और सहयोग की संभावनाओं पर मध्यपूर्व की स्थिति की परछाईं पड़ी है । उधर यातायात के लिए स्वेज नहर का खुलना बाकी रहता है । इस क्षेत्र में सैनिक संघियों की नीति ने राष्ट्रों को आपस में बांट दिया है और एशिया में अधिकाधिक युद्ध सामग्री जुटाई जाने लगी है । फिर भी यह देख कर कि इस क्षेत्र में संघर्ष का और अधिक विस्तार नहीं हुआ हम संतुष्ट होना चाहिए ।

५. भूतपूर्व ब्रिटिश उपनिवेश गोल्ड कोस्ट और इस के साथ अंग्रेजी शासन के अधीन टोगोलैंड का प्रदेश अब घाना नामक स्वतंत्र और सर्वाधिकार सम्पन्न राष्ट्र के रूप में और राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में उदित हुआ है, इस बात से भारत सरकार और भारत की जनता को बहुत खुशी हुई है ।

६. हम संयुक्त राष्ट्र म सूडान, मोरक्को, ट्यूनीसिया, जापान तथा घाना के प्रवेश का स्वागत करते हैं । मंगोलिया के बराबर बाहर रहने और चीन के अधिकृत प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र में स्थान न दिये जाने के कारण हमें क्षोभ होता है और इस स्थिति का प्रतिकार करने में हम बराबर प्रयत्नशील हैं ।

७. हम आशा करते हैं कि मलाया शीघ्र ही एक स्वतंत्र देश बन जायगा और ऐसा होने से उपनिवेशवाद का प्रभाव और कम हो जायगा और एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता की सीमाएँ विस्तृत हो सकेंगी ।

८. संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के ११वें सत्र में मध्यपूर्व, अल्जीरिया और साइप्रस-सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर होने वाले विवादों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावोत्पादक और उपयोगी योगदान दिया है और इन समस्याओं का शान्तिपूर्ण हल ढूँढ़ने और कार्यप्रणाली तय करने में सहायता दी है । निःशस्त्रीकरण का कार्य आगे नहीं बढ़ा है किन्तु संयुक्त राष्ट्र ने एकमत से अपने प्रयत्न जारी रखने और भारत के सुझाव समेत सभी सुझावों पर विचार करने का निश्चय किया है । भारत सरकार को खुशी है कि वह इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में सहायक हो सकी ।

९. हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेंसी के प्रारम्भिक आयोग का सदस्य था । इसलिए हमें इस बात का संतोष है कि इस एजेंसी की अब स्थापना हो गई है । हमारी यह कामना तथा आशा है कि अणुशक्ति का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों में होगा और विध्वंसक कार्यों में इस का प्रयोग बन्द हो सकेगा ।

१०. अपने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की यात्रा का मुझे सुख और सौभाग्य प्राप्त हुआ । उपराष्ट्रपति ने महामहिम नेपाल नरेश महेंद्र वीर विक्रम शाह के राज्याभिषेक के अवसर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया था । आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में नेपाल सरकार तथा वहाँ की जनता के प्रयत्नों का प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और हमें खुशी है कि हम उन की पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने में टेकनिकल तथा आर्थिक सहायता दे सके ।

११. भारत में बुद्ध जयन्ती-सम्बन्धी समारोहों के कारण हमें अपने देश में दलाई

लामा तथा पंचन लामा और संसार के विभिन्न भागों के बौद्ध नेताओं के स्वागत का सुअवसर मिला। इस समारोह ने हमें और संसार को भगवान बुद्ध के शान्ति तथा कृपा के संदेश का फिर से स्मरण कराया। आज विश्व को इस संदेश की अत्यधिक आवश्यकता है।

१२. अपने देश में अनेक सम्मानित आगन्तुकों का स्वागत करने और उन का परम्परागत आतिथ्य करने का भारत सरकार और इस देश के लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे इन सम्मानित अतिथियों में महामहिम ईरान के शहनशाह तथा सम्राज्ञी, महामहिम इथोपिया के सम्राट्, सीरिया के राष्ट्रपति शुक्रि-अल-कुवतली, कम्बोडिया के राजकुमार परमश्रेष्ठ नरोदम सिंहनूक, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन, नेपाल और डेन्मार्क के प्रधान मंत्रीगण, जर्मनी के संघीय गणतंत्र के उपचांसलर, सोवियत संघ के उपप्रधान मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री, सूडान के उपप्रधान मंत्री और अमरीका, फ्रांस तथा ब्रिटेन के परराष्ट्र मंत्री शामिल हैं। १९५६ में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के अध्यक्ष, डा० जोज माजा, और संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री भी हमारे सम्मानित अतिथियों में शामिल थे। बर्मा, चीन, चेकोस्लोवाकिया, डेन्मार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नौर्वे, पोलैंड, स्वीडन, सीरिया और यूगेंडा से संसदीय, सांस्कृतिक व्यापारिक तथा सद्भावना-सम्बन्धी प्रतिनिधिमंडल भी हमारे देश में आए।

१३. भारतीय उपराष्ट्रपति ने सोवियत संघ, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रूमानिया, बल्गारिया, पूर्वी अफ्रीका, केन्द्रीय अफ्रीकी संघ, इंडोनेशिया तथा जापान की यात्रा की और सभी देशों में उन का हार्दिक स्वागत हुआ।

१४. राष्ट्रपति आइजन्हावर के निमंत्रण पर हमारे प्रधान मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा से तथा अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधान मंत्री में विचार-

विनिमय के फलस्वरूप हमारे दोनों देशों के बीच अधिक सद्भावना हुई तथा एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिली। मेरी सरकार को विश्वास है कि इस के द्वारा पारस्परिक सम्मान तथा सद्भावना के आधार पर दोनों देशों में अधिकाधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा।

१५. केनेडा के प्रधान मंत्री, श्री लुई सेंट लारां, के निमंत्रण पर हमारे प्रधान मंत्री ने केनेडा की भी यात्रा की। यह यात्रा केनेडा और हमारे देश के बीच सुखद सम्बन्धों को और दृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुई है। हमारे दोनों देशों में सदा निकट के और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं।

१६. मेरी सरकार को खेद है कि दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति की समस्या को सुलझाने और अफ्रीकियों तथा भारतीय प्रवासियों के विरुद्ध भेदभाव की नीति को दूर करने के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं की जा सकी। मेरी सरकार के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर इस समस्या पर विचार किया। बातचीत द्वारा इस समस्या का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सम्बद्ध सरकारों से फिर अपील की है। पहले की तरह भारत सरकार ने फिर स्वेच्छा से इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

१७. मेरी सरकार को हार्दिक खेद है कि गोवा अभी भी पुर्तगाली सरकार की औपनिवेशिक चौकी के रूप में बना है और वहां प्रत्येक प्रकार की स्वाधीनता का दमन किया जा रहा है और अधिक उन्नति अवरुद्ध है। मेरी सरकार की यह दृढ़ नीति है कि गोवा को औपनिवेशिक प्रभुत्व से मुक्त होना चाहिए और भारत की स्वाधीनता में साझेदार होना चाहिए।

१८. मेरी सरकार को खेद है कि पाकिस्तान से इस के सम्बन्धों में बराबर कठिनाइयां पैदा हो रही हैं और पाकिस्तान में भारत-विरोधी और जिहाद के आन्दोलनों में कुछ भी कमी नहीं आई। भारत सरकार और देश के

लोगों का दृष्टिकोण यह है कि हम घृणा का उत्तर घृणा से नहीं देंगे, किन्तु अपने न्यायोचित हितों तथा देश की रक्षा करते हुए दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्रोत्साहन देने में प्रयत्नशील रहेंगे। पूर्वी पाकिस्तान से भारत में लोगों की निकासी गत वर्ष बराबर होती रही और इस समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया। कुल मिला कर पूर्वी पाकिस्तान से ४० लाख से ऊपर लोग भारत में आ चुके हैं और इन लोगों के आ जाने से हमारे देश पर, विशेषकर पश्चिम बंगाल की सरकार पर, भारी बोझ पड़ा है।

१६. पाकिस्तान सरकार के आवेदन पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में काश्मीर के मामले पर विचार किया गया। भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट और निर्विवाद शब्दों में व्यक्त की गई है, अर्थात् अक्टूबर, १९४७ से जम्मू और काश्मीर राज्य भारतीय संघ के दूसरे राज्यों की तरह देश का एक वैधानिक भाग रहा है और अब भी है। काश्मीर में जो स्थिति पैदा हुई है उस का कारण, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पास किये गये प्रस्तावों में निहित समझौतों की अवहेलना करके, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण और भारतीय संघ के भू-भाग पर अवैध रूप से अधिकार कर लेना है। सुरक्षा परिषद् ने गत मास अपने तत्कालीन सभापति को भारत और पाकिस्तान की सरकारों से बातचीत करने के लिए इन देशों में भेजने का निश्चय किया। अपनी साधारण नीति के अनुसार भारत सरकार ने स्वीडन निवासी श्री यारिंग का, जिन के शीघ्र ही यहां आने की आशा है, स्वागत तथा उन का आतिथ्य-सत्कार करने की सहमति दी है।

२०. अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, जिस में पहले सुधार के लक्षण दृष्टिगोचर होते थे, अब कम आशाजनक दिखाई देती है। फिर भी हमारे देश के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बराबर बने हैं, यद्यपि विश्व की स्थिति में बिगाड़ का पूर्व के देशों के शान्ति-

पूर्ण सम्बन्धों, परस्पर सहयोग तथा आर्थिक विकास पर दूषित प्रभाव पड़ा है। शक्ति के संतुलन पर आधारित सैनिक गुटों की नीति के कारण विशेष रूप से एशिया में तनाव बढ़ा है, शास्त्रास्त्रों में वृद्धि हुई है और शीत युद्ध के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। मेरी सरकार की बराबर यह दृढ़ धारणा है कि शान्तिपूर्ण बातचीत और पारस्परिक समझौतों द्वारा ही विश्व की समस्याओं को ठीक और आशाजनक ढंग से सुलझाया जा सकता है।

२१. गत वर्ष राज्यों के पुनर्गठन का कार्य समाप्त कर लिया गया और यह कार्य, जिस के कारण देश के कुछ भागों में दुर्भाग्यवश भावातिरेक के प्रदर्शन हुए, अब सम्पन्न हो चुका है। गत वर्ष ही पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि सफलतापूर्वक समाप्त हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना को चालू किया गया। इस योजना में खाद्यों के उत्पादन पर पहले की तरह जोर दिया गया है किन्तु इस के साथ ही देश के औद्योगिक विकास, विशेषकर बड़े उद्योगों की स्थापना पर अधिक बल दिया गया है। सामुदायिक योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का देहाती इलाकों में आश्चर्यजनक तेजी से विस्तार हुआ है। इन सेवाओं के अन्तर्गत अब दो लाख बीस हजार गांव और १२ करोड़ ६० लाख जनसंख्या आती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में छोटे और घरेलू उद्योगों की उन्नति पर विशेष जोर दिया गया है।

२२. खनिज पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप देश की आशाजनक खोज हुई है और राजस्थान तथा बिहार में यूरेनियम धातु का पता लगा है। थोरियम और यूरेनियम की भारी मात्रा में उपलब्धि के कारण इन धातुओं के हमारे ज्ञात साधन दुगुने से भी अधिक हो गये हैं। हमारे अणु शक्ति विभाग ने भी प्रगति की है और भारत का पहला अणु रिक्टर गत वर्ष चालू हो गया। सोवियत

संघ से बाहर एशिया में स्थापित होने वाला यह पहला अणु रिएक्टर है।

२३. दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष समाप्त होने वाला है। विगत वर्ष में कुछ कठिनाइयां हमारे सामने आई हैं। कुछ चीजों के भाव ऊंचे चढ़े हैं और विदेशी विनिमय के हमारे साधन संकुचित हो गए हैं। यह गतिविधि देश के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में बढ़ते हुए उत्पादन की परिचायक है। देश में धन लगाने पर जोर और अधिक उपभोक्ता पदार्थों की अधिक मांग त्वरित विकास की प्रक्रिया का आवश्यक अंग है और एक हद तक इस प्रकार का दबाव इस बात का द्योतक है कि विकास के हित में देश के साधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। किन्तु हमें सावधान रहना चाहिए कि यह दबाव बहुत अधिक न होने पावे। भावों के चढ़ाव को रोकने के लिए और विदेशी विनिमय के साधनों के ह्रास की रोक थाम के लिये सरकार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये दृढ़प्रतिज्ञ है।

२४. इस दिशा में सरकार के सामने प्रमुख समस्या विदेशी विनिमय के साधनों की सुरक्षा तथा वृद्धि की है। जिस देश में मशीनें तैयार करने की काफी क्षमता न हो, उसे औद्योगीकरण के लिए आवश्यक रूप से विदेशी विनिमय अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है। विदेशी विनिमय पूंजी में सहसा अधिक वृद्धि संभव नहीं, इसलिए देश के साधनों के विकास के हित में आरम्भ में विदेशी सहायता आवश्यक होती है। फिर भी अधिकाधिक विदेशी विनिमय उपार्जित करना और आयात में मितव्ययता से काम लेना प्रत्येक देश के लिए अनिवार्य है। अमरीकी सरकार से हाल में ही जो समझौता हम ने किया है और जिस के अनुसार हमें विपुल मात्रा में गेहूं, चावल और रूई उधार मिल सकेगा, उस से हमें चढ़ते हुए भावों को रोकने और अपनी योजना को आगे बढ़ाने में सहायता

मिलेगी। हमें आशा है कि विष्व बँक सरीखी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा मित्र देशों से भी हमें काफी वित्तीय सहायता मिलेगी। फिर भी यह निर्विवाद है कि विकास के कामों के लिये आवश्यक साधनों को हमें अपने बल पर ही जुटाना होगा और इस के लिए उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से हमें जनता को संगठित करना होगा।

२५. दूसरी योजना में औद्योगीकरण और आर्थिक व्यवस्था के विविधीकरण को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिये खाद्य, कपड़ा और उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल सम्बन्धी आधारभूत पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है। इस योजना में अधिक धन लगाने पर भी जोर दिया गया है और रोजगार के साधनों का विस्तार इस के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। रोजगार के बढ़ाने और धन लगाने से जो आयात होगी वह अधिकतर खुराक और कपड़े पर खर्च होगी। इसलिये इन दोनों चीजों के उत्पादन में वृद्धि द्वारा ही योजना को, मुद्रावाहून्य का संकट उपस्थित किए बिना आगे बढ़ाया जा सकता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि विकास के क्षेत्र में हमारे प्रयासों का प्रमुख आधार है। इस काम के लिए जनता के प्रत्येक वर्ग के लोगों का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।

२६. १९५७-५८ वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े आप के सम्मुख रखे जायेंगे जिस से कि आप इस पर अपना मत दे कर आलोच्य वर्ष के एक भाग के लिये खर्च करे की अनुमति दे सकें। इस के अतिरिक्त केरल राज्य के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के आंक आप का अनुमोदन प्राप्त करने के हेतु आप के सामने रखे जायेंगे।

२७. संसद् का यह सत्र स्वल्प होगा और इस में कोई बड़ा अथवा विवादास्पद विधान हाथ में नहीं लिया जाएगा। कुछ अण्व्यादेश जो विगत सत्र के बाद जारी किए गए थे संसद् के समक्ष रखे जायेंगे।

२८. पांच वर्ष हुए इस महान देश के मतदाताओं की प्रतिनिधि स्वरूप यह संसद् चुनी गई थी और इस ने देश के कल्याण तथा प्रगति के लिए और विश्व में सहयोग तथा शान्ति-स्थापन के लिये यत्न किया है। इस यत्न का सुखद फल हुआ है जिसे हम देश में चारों ओर देखते हैं। जो सफलताएँ आपने इस अवधि में प्राप्त की हैं उन पर, संसद् के सदस्यगण, मैं आप को बधाई देना चाहता हूँ। परन्तु हम में से कोई भी निश्चिन्त हो कर बैठ नहीं सकता क्योंकि नवीन और सम्पन्न भारत के निर्माण की कहानी सदा घटित होती रहेगी, जिस से इस देश की जनता को सुख प्राप्त होगा और विश्व-शान्ति तथा सहयोग के पक्ष को बल मिलेगा।

२९. मैं आशा करता हूँ कि भगवान बुद्ध का सन्देश, जिन की जयन्ती हम ने हाल में ही मनाई थी, तथा हमारे राष्ट्रपिता की आत्मा हमें सत्प्रेरणा देती रहेगी।

(Text of the President's Address in English)

Members of Parliament, I am addressing you today after a full year, a year which has witnessed significant happenings in the world and considerable developments in our own country. We are meeting at a time when general elections are being held all over the country, and a new Parliament is coming into being as a result of these elections. This is the last occasion when I am addressing this Parliament. Some of you will come back to represent your constituencies in the new Parliament and some of you may not return. But I have no doubt that wherever your field of work may lie, it will be dedicated to the great task of building up this country of ours. I wish you success and good fortune in your field of activity.

2. Since I addressed you last, the world has seen a period of high tensions, particularly in the Middle East, and of conflict ending in the invasion of Egypt. The intervention of the

United Nations and the impact of world opinion resulted in the withdrawal of the invading armies from Egypt; but the conflict has not only done great damage to Egypt but has added to the tensions which were showing signs of relaxation, and has left in its wake many problems to be resolved. Our country, which is deeply involved both on account of her concern for world peace and co-operation and her own interest, has sought to assist in resolving these difficulties. India has accepted greater burdens including participation in the United Nations Emergency Force constituted by the decision of the General Assembly of the United Nations which called for the withdrawal of the invading forces.

3. In Central Europe, the events in Hungary have disturbed us greatly and here, as elsewhere, we have stood for the withdrawal of foreign forces and against their use against peoples and national movements. At the same time, we have used our best efforts to assist in finding solutions to the problem at its various stages and extended our sympathy and our token of assistance to the people of Hungary.

4. The position in the Middle East casts its shadow over the prospects of cooperation and peace and the Suez Canal awaits opening for traffic. The policy of military pacts has divided the nations in this region and brought the apparatus of war more and more into Asia. We must, however, note with relief that the conflict in this region did not grow to greater dimensions.

5. Our Government and people rejoice in the fact that the former British colony of the Gold Coast, along with the former Trust Territory of Togoland under British administration, has now been constituted into the independent and sovereign State of Ghana and a full member of the Commonwealth of Nations.

6. We welcome the admission of Sudan, Morocco, Tunisia, Japan and Ghana to the United Nations. The

continued exclusion of Mongolia and the denial to the rightful representatives of China of their place in the United Nations cause us deep concern and we continue to devote our endeavours to remedy this situation.

7. We hope that Malaya will soon become a free and independent State and this will further limit the sphere of colonialism and extend the area of national freedom in Asia.

8. In the United Nations, the Indian Delegation, in the Eleventh Session of the General Assembly, has made effective and useful contributions in the prolonged debates on crucial issues in regard to the Middle East, Algeria and Cyprus, and contributed to peaceful solutions and procedures in respect of them. Disarmament has made no progress, but the United Nations unanimously resolved to continue its efforts to consider all proposals before it, including the proposals made by India. The Government of India are happy to have been able to assist in promoting this resolution.

9. Our country, which was a member of the Preparatory Commission of the International Atomic Energy Agency, can derive satisfaction that the Agency has now been established. May it fulfil the hopes that atomic energy will be harnessed for peaceful uses and also diverted from destructive purposes.

10. I had the happy privilege of visiting our near neighbour, Nepal; and the Vice-President represented our country at the Coronation of His Majesty King Mahendra Bir Bikram Shah. The endeavours of the Nepal Government and people for economic and social development have our full sympathy, and we are happy that we have been able to extend technical and economic assistance to them in the implementation of their Five Year Plan.

11. The Buddha Jayanti celebrations in India gave us the opportunity of welcoming in this country the Dalai

Lama and the Panchen Lama, as well as leaders of Buddhism from different parts of the world. These celebrations reminded us and the world afresh of the great message of peace and compassion of the Buddha, which is so much needed in the world today.

12. We have been privileged to receive in our country many distinguished visitors to whom my Government and the people of India have extended their traditional hospitality. Among these eminent guests of ours have been Their Imperial Majesties the Shahenshah and the Empress of Iran, His Imperial Majesty the Emperor of Ethiopia, President Shukri El-Kuwatly of Syria, His Royal Highness Prince Norodom Sihanouk of Cambodia, Prime Ministers of Burma, Ceylon, Indonesia, China, Nepal and Denmark, the Vice-Chancellor of the Federal Republic of Germany, the Deputy Prime Minister and Defence Minister of the Soviet Union, the Deputy Prime Minister of Sudan and the Foreign Ministers of the United States, France and the United Kingdom. The President of the United Nations General Assembly for 1956, Dr. Jose Maza, and the Secretary General of the United Nations were also among our distinguished visitors. Parliamentary, cultural, trade and other goodwill delegations from Burma, China, Czechoslovakia, Denmark, Germany, Indonesia, Japan, Norway, Poland, Sweden, Syria and Uganda have also visited our country.

13. The Vice-President paid visits to the Soviet Union, Poland, Czechoslovakia, Hungary, Rumania, Bulgaria, East Africa, the Central African Federation, Indonesia and Japan and received a very warm welcome everywhere.

14. My Prime Minister visited the United States at the invitation of President Eisenhower. The visit and the talks between the President of the United States and my Prime Minister have assisted in the promotion of understanding between our two countries and greater appreciation of each

other's point of view. My Government feel confident that it will lead to increasing co-operation in all fields on the basis of mutual respect and understanding.

15. My Prime Minister also visited Canada at the invitation of Mr. Louis St. Laurent, the Prime Minister of Canada. His visit has helped to further enrich the relations between Canada and our country, which have always been very friendly and close.

16. My Government regret that no progress has been made in regard to the solution of the problem of "apartheid" and discrimination against Africans and people of Indian origin in South Africa. This problem once again received the consideration of the United Nations at the instance of my Government. A further appeal to the Governments concerned to find a solution by negotiations has been made by the United Nations. The Government of India, as in the past, has readily subscribed to this resolution.

17. My Government deeply regret that Goa still continues to be an unhappy colonial outpost of the Portuguese Government, where every kind of liberty is suppressed and economic stagnation prevails. It is the firm policy of my Government that Goa should become free from colonial domination and should share in the freedom of the rest of India.

18. My Government regret that its relations with Pakistan continue to present difficulties and there has been no abatement in Pakistan of the campaigns of hatred and 'jehad'. The policy of the Government of India and the general approach of our people have been that we shall not respond to these with hatred, but shall continue our endeavours to promote friendly relations while defending our land and our legitimate interests. The exodus of people from East Pakistan to India' continued throughout this past year and assumed alarming proportions. Altogether, over four million people have come from East Pakistan to India, and these persons have cast a

heavy burden on our country and, more especially, on the State of West Bengal.

19. The problem of Kashmir was considered by the Security Council of the United Nations once again, at the request of the Government of Pakistan. The Government of India's position has been stated in clear and unambiguous terms, that the Jammu and Kashmir State is and has been a constituent State of the Indian Union since October 1947, like other States which acceded to the Union. The present situation in Kashmir has arisen from aggression and on illegal occupation of Union territory by Pakistan in violation of international law and agreements and engagements reached in pursuance of United Nations resolutions. The Security Council has resolved last month to send its then President to Pakistan and India to confer with the two Governments. The Government of India, in accordance with its general policy, has agreed to receive and extend hospitality to Mr. Jarring of Sweden who is expected to arrive here soon.

20. The world situation as a whole, which was beginning to show some signs of improvement, gives us cause for less optimism at present. Our own country, however, continues to have friendly relations with all countries, but the deterioration in the world situation has adverse results on the development of peaceful relations and co-operation and economic development in our part of the world also. More particularly, the policy of military pacts based upon the balance of power, mutual suspicion and fear, has increased tensions in Asia and has led to the increase of armaments and extended the area of cold war. It continues to be the firm belief of my Government that only by a peaceful approach and agreed settlements can be found the right and hopeful way for solutions of the world's problems.

21. During the past year, the reorganisation of the States was completed, and this great task which had unfortunately roused much passion in some

parts of the country, was accomplished. During the past year also, the First Five Year Plan was successfully completed and the Second Five Year Plan begun. This Plan, while continuing to lay stress on greater food production, emphasises the need for industrial development, more especially in regard to heavy industry. The Community Projects and the National Extension Service have been extended with phenomenal rapidity over our rural areas and now cover two hundred and twenty thousand villages and a rural population of one hundred and twenty-nine millions. In the community development scheme, special stress is being laid on the development of small-scale and cottage industries.

22. Mineral surveys have yielded promising discoveries of oil, and many new deposits of uranium ore have been located in Rajasthan and Bihar. The finds of thorium and uranium minerals in large quantities have more than doubled our known reserves of these minerals. The work of our Atomic Energy Department has made great progress, and India's first atomic reactor began operations last year. This is the first reactor to go into operation in Asia, outside the Soviet Union.

23. We are about to complete the first year of the second Five Year Plan. Certain stresses and strains have emerged in the course of this year. Prices of certain commodities have risen and there has been a substantial draught on the foreign exchange resources of the country. These factors reflect the growing tempo of development in the country, in the public as well as in the private sectors. The growth of internal demand for consumption and for investment is a concomitant of rapid development and, up to a point, the emergence of such pressures is a sign that the resources of the country are being stretched in the interests of development. It is, however, essential to ensure that these pressures do not go too far. Government are determined to take appropriate measures to restrain the rise in prices and to

reduce the drain on foreign exchange resources.

24. The major problem before the country in this context is that of conserving and increasing its foreign exchange resources. For a country which starts with insufficient facilities for producing machinery and equipment, a plan of industrialisation necessarily involves heavy foreign exchange expenditure. Since it is difficult in the short run to enlarge foreign exchange earnings substantially, developing economies require an inflow of external resources in the initial stages. It is, however, incumbent on the country concerned to earn the maximum foreign exchange it can and to exercise the utmost economy in the matter of imports. The recent agreement with the United States Government, under which large quantities of wheat, rice and cotton will be available to us on credit terms, will help in checking the rise in prices and will contribute to the furtherance of the Plan. Considerable external finance will, we expect, be forthcoming from international agencies like the World Bank and from friendly countries. Nevertheless, the bulk of the resources required for development must come from within the country and the community has to be organised for a big production effort to make this possible.

25. The second Plan gives high priority to industrialisation and to the diversification of the economic structure. This, in turn, requires a substantial increase in the production of basic necessities like food and cloth and of raw materials required for the developing industries. The Plan calls for more investment, and one of its principal aims is to enlarge employment opportunities. New incomes created by investment and employment are mostly spent on food and cloth and it is only if their supplies can be increased rapidly that the Plan can go forward without creating an inflationary situation. An increase in agricultural production thus constitutes the pivot of developmental effort and for this we need the fullest cooperation of every section of the community.

26. A statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the financial year 1957-58 will be laid before you for the purpose of passing votes on account authorising expenditure for a part of that year. In addition, a similar statement in respect of the Kerala State will also be laid before you for passing a vote on account for a part of the year for that State.

27. This session of Parliament will be a brief one and no major or controversial legislation will be taken up during this session. Some Ordinances which have been promulgated since the last session will be placed before Parliament.

28. Five Years ago this Parliament came into existence representing the vast electorate of this great country, and it has laboured for the well-being and advancement of India and for peace and cooperation in the world. These labours have produced substantial results which we see all round us in the country, and I wish to offer you, Members of Parliament, my congratulations on the great tasks that have been accomplished. But there is no resting place for any of us and the great story of the building up of a new and prosperous India will continue to unfold itself, bringing happiness to all our people and serving the cause of world peace and co-operation.

29. I earnestly trust that the message of the Buddha, whose anniversary we recently celebrated, will ever guide us, and the spirit of the Father of the Nation will continue to inspire us.

REFERENCE TO THE PASSING AWAY OF SHRI B. G. KHER

MR. CHAIRMAN: Before we pass on to other business, I should like to refer to the great loss which our country has suffered by the passing away of Shri B. G. Kher, who was for some months a Member of the Rajya

Sabha. He had a very distinguished public career. I met him for the first time in 1926 when he was a practising Solicitor there. The last letter which I received from him was a few days before his death, regarding the award of a prize to the best Tilak biography. Tilak had a great influence on him, as his very name Bal Gangadhar suggests. Actually, towards the end of his life he was engaged as the Chairman of the Gandhi Smarak Nidhi, engaging himself in humanitarian work of great importance. Tilak and Gandhi have been the formative influences so far as his life was concerned. Whether as a valiant fighter for freedom, whether as Chief Minister of Bombay State or as High Commissioner in London, his work was characterised by courage, character, integrity and devotion. A clean, honest man of singular affability and charm, we mourn the loss of a great and noble son of this country.

As a mark of respect to his memory, I request the House to stand up for a minute.

(The House then stood in silence for one minute.)

PAPERS LAID ON THE TABLE

STATEMENT OF BILLS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT

SECRETARY: Sir, I beg to lay on the Table a statement showing the Bills which were passed by Parliament during the Fifteenth Session of the Rajya Sabha and assented to by the President.

Statement

1. The Indian Tariff (Amendment) Bill, 1956.
2. The Abducted Persons (Recovery and Restoration) Continuance Bill, 1956.
3. The Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 1956.